



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १, अंक १६]

गुरुवार, मे ७, २०१५/वैशाख १७, शके १९३७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

वित्त विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मे २०१५.

क्रमांक संकीर्ण १०.१४/१०५/प्र.क्र. ७३/अर्थोपाय.—भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड यांच्याकडून भारत सरकारच्या असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-३, उपखंड (ii) क्रमांक १८३७ मध्ये दिनांक ६ ऑगस्ट २०१३ रोजी प्रसिद्ध झालेली खालील अधिसूचना माहितीसाठी याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात पुनः प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :—

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त 2013।

का. आ. 2406(अ).—केंद्रीय सरकार ने अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का. आ. 906(अ), तारीख 5 जून 2007 द्वारा नेशनल स्पार्ट एक्सचेंज लिमिटेड में व्यापारित वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए एक दिन की अवधि की सभी अग्रिम संविदाओं को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रचालन से उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन छूट दी थी ;

और चूंकि, नेशनल स्पार्ट एक्सचेंज लिमिटेड ने विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन किया था इसलिए केंद्रीय सरकार द्वारा तारीख 27 अप्रैल 2012 को एक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी ;

और नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना के उत्तर पर विचार करने के पश्चात केंद्रीय सरकार के अपने पत्र सं. 12/3/2003-आईटी (वाल्सू. II) तारीख 12 जुलाई 2013 द्वारा नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड को निम्नलिखित निदेश दिया था :—

(i) संबंधित प्राधिकारी से आगे और अनुदेश मिलने तक कोई और आगे/ताजा संविदाएं प्रारंभ नहीं की जाएंगी ।

(ii) सभी विद्यमान संविदाओं का निपटारा देय तारीखों पर किया जाएगा ।

और नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड ने अपने परिपत्र निर्देश सं. एनएसईएल/टीआरडी/2013/065, तारीख 31 जुलाई 2013 द्वारा आगे और सूचना तक ई-शृंखला संविदाओं के सिवाए सभी संविदाओं में व्यापार को निलंबित कर दिया और 31 जुलाई 2013 से सभी लंबित संविदाओं के परिदान और निपटारे का विलय करने और उसे पन्द्रह दिन की अवधि के लिए आस्थगित करने का विनिश्चय किया है ;

और उसके परिणामस्वरूप, संविदाओं में बकाया स्थितियों का निपटारा पन्द्रह दिन की समाप्ति के पश्चात् ही परिदान और संदाय करके और अग्रिम संविदाओं के निपटारे का विलयन और आस्थगन करके किया जाएगा, नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड की इस बात से यह धारणा बनी है कि इसके द्वारा संदाय करने में व्यतिक्रम हो सकेगा और इससे नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड के विभिन्न बाजार भागीदारों के मस्तिष्क में भ्रम और असंतोष पैदा हुआ है ।

2. इसलिए अब केंद्रीय सरकार ने, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का, आ. 906(अ), तारीख 5 जून 2007 में, उसकी शर्त (v), जो समय-समय पर अतिरिक्त शर्त अधिरोपित करने के इसके अधिकार को आरक्षित करती है, के निबंधनों में आंशिक परिवर्तन करके वस्तु बाजार भागीदारों के हितों की संरक्षा के लिए नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड पर निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त अधिरोपित करती हैं, अर्थात् :—

(i) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड पर विद्यमान ई-शृंखला में कोई व्यापार और किसी वस्तु की कोई आगे और या ताजा एक दिन अग्रिम संविदा नहीं की जाएगी ;

(ii) नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड पर सभी बकाया एक दिन अग्रिम संविदाओं का निपटारा अग्रिम बाजार आयोग के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा और अग्रिम बाजार आयोग द्वारा इस बाबत जारी किया गया कोई भी आदेश या निदेश नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड पर और नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड से संबद्ध किसी व्यक्ति, मध्यवर्ती या भांडागार पर बाध्यकारी होगा और इस प्रयोजन के लिए अग्रिम बाजार आयोग ऐसे उपाय करने के लिए प्राधिकृत है जो वह उचित समझे ।

[फा. सं. 12/3/2003-आईटी वाल्सू. (II)]

गंगा मूर्ति,
प्रधान सलाहकार ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August 2013

S. O. 2406(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government *vide* notification Number S. O. 906(E), dated 5th June 2007, had exempted all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on the National Spot Exchange Limited from the operation of the provisions of the said Act, subject to the conditions specified therein ;

And whereas, as the National Spot Exchange Limited had contravened the specified conditions, a show cause notice dated 27th April 2012 was issued by the Central Government ;

And whereas, after considering the reply given by the National Spot Exchange Limited to the said show cause notice, the Central Government *vide* its letter No. 12/3/2003 IT (Vol. II), dated 12th July 2013 had directed National Spot Exchange Limited as under :—

(i) no further/fresh contracts shall be launched till further instructions from the concerned authority ;

(ii) all existing contracts will be settled on due dates.

And whereas, the National Spot Exchange Limited *vide* its circular reference No. NSEL/TRD/ 2013/065, dated the 31st July 2013 suspended trading in all contracts except 'e-series' contracts until further notice, and has decided to merge the delivery and settlement of all pending contracts with effect from the 31st July 2013 and to defer it for a period of 15 days ;

And whereas, as a consequence thereof, the positions outstanding in the contracts will be settled by way of delivery and payment only after the expiry of 15 days, and by merging and deferment of settlement of forward contracts, the National Spot Exchange Limited has given an impression that there may be default in making payment by it and this has created confusion and unrest in the minds of various market participants of National Spot Exchange Limited.

2. Now, therefore, in partial modification of the Government of India notification Number S. O. 906(E), dated 5th June 2007, the Central Government, in terms of condition (v) thereof, which reserves its right to impose additional conditions from time to time, hereby imposes the following additional conditions upon the National Spot Exchange Limited to protect the interests of commodity market participants, namely :—

(i) no trading in the existing e-series contracts, and no further or fresh one day forward contracts in any commodity, shall be undertaken on National Spot Exchange Limited without prior approval of the Central Government ;

(ii) Settlement of all outstanding one day forward contracts at National Spot Exchange Limited shall be done under the supervision of forward Markets Commission and any order or direction issued by the Forward Market Commission in this regards shall be binding upon the National Spot Exchange Limited and any person intermediary or warehouse connected with the National Spot Exchange Limited and for this purpose the Forward Markets Commission is authorized to take such measures, as it deems fit.

[F. No. 12/3/2003 IT (Vol. II)]

GANGA MURTHY,
Principal Adviser.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

व. कृ. पाटील,
शासनाचे उप सचिव.